राष्ट्रीय दैनिक

प्रातःकिरण

दिल्ली एवं पटना से प्रकाशित

हर खबर पर पकड़

/Pratahkiran /Pratahkiran /Pratahkiran

11 हार्दिक पांड्या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से ...

जब आप देश के बाहर होते हैं तो राजनीति पीछे रह जाती है, विदेश मंत्री की राहुल 12

वर्ष : 11 | अंक : 25 | पटना, सोमवार, 05 जून, 2023 | विक्रम संवत् 2080 | पेज : 12 | मूल्य ₹ : 03.00 | www.pratahkiran.com

मौसम अधिकतम तापमान 42°C न्यूनतम तापमान 27.0°C

हो सकती 30% नहीं हो सकती 50% कह नहीं सकते 10%

बाजार

सोना 59,995

चांदी 72,500

सेंसेक्स 57,635

निफ्टी 16,986

तेजस्वी का बड़ा ऐलान: जल्द ही 16 हजार पदों पर होगी नई बहाली

प्रातः किरण संवाददाता

पटना। विभिन्न विभागों में बहाली को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इस कड़ी में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। रविवार को ग्रामीण पथ विकास अधिकरण की 22वीं आम सभा और विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि जल्द ही ग्रामीण कार्य विभाग में 16 हजार नियुक्तियां होंगी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। ग्रामीण सड़कों से लेकर पुलों के निर्माण को लेकर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामीण इलाकों की सड़कें सबसे अधिक खराब हैं, सबसे पहले वहां की सड़कों का निर्माण होगा। तेजस्वी ने बताया कि निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग में जल्द ही 16 हजार नई बहाली होगी।

विपक्षी दलों की बैठक पर बोलें–किसी को घबराने की जरूरत नहीं : विपक्षी दलों की बैठक को लेकर उठ रहे सवाल पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दो टूक में कहा है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सही समय पर सभी चीजें साफ हो जाएंगी। दरअसल, तेजस्वी यादव पटना के बापू सभागार में आयोजित पान महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान

विपक्षी एकता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी ने दावा किया कि 12 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक बहुत अच्छे तरीके से होगी। सभी चीजें साकारात्मक हैं और इसको लेकर किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। विपक्ष के खेमें में सभी चीजें पॉजिटिव हैं किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बैठक से खरगे और राहुल गांधी के दूरी बनाने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि इंतजार कीजिए, सभी चीजें खुलकर नहीं बताई जा सकती हैं। वहीं, बालासोर रेल हादसे को लेकर तेजस्वी ने केंद्र को निशाने पर लिया है। तेजस्वी ने कहा हादसे को जो तस्वीरें सामने आई है, वह देखकर कलेजा फटने लगता है। बच्चों, महिलाओं, जवान और दूसरी यात्रियों की मौत हुई है। केंद्र सरकार लगातार यह दावे करती रही है कि उन्होंने रेलवे में सेफ्टी को लेकर बहुत काम किया है। लेकिन इस हादसे में यह सारे दावे पूरी तरह से गलत साबित हो गए हैं। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री के द्वारा दोषियों पर कार्रवाई करने की बात को लेकर जवाब देते हुए कहा महिला पहलवानों के लिए अब तक कोई कार्रवई नहीं की गई, ऐसे में इस रेल हादसे को लेकर क्या कार्रवाई करेंगे, यह आनेवाले समय बताएगा। क्योंकि अभी तक इस हादसे को कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। तेजस्वी बिहार से जुड़े रेल मंत्रियों का जिक्र किया। उन्होंने रामविलास पासवान जी रेल मंत्री रहे। लालू जी और नीतीश जी भी रेल मंत्री रह चुके हैं। उस समय इतना प्राइवेटाइजेशन नहीं था। आज रेलवे का प्राइवेटाइजेशन पर इतना जोर है कि बाकि चीजों को दरकिनार कर दिया गया है। विपक्षी एकता के प्रयास में मिल रही कामयाबी से गदगद हैं। उनकी पहली कोशिश कामयाब रही है। अब तक विभिन्न दलों के पांच प्रमुख विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात और बातचीत हुई है। सभी की ओर से सकारात्मक उत्तर मिला है। आक्रमजनक ढंग से एकला चलने वाली ममता बनर्जी भी अब अपना हृदय छोड़ने को तैयार हो गई हैं। अब यह जान लेना जरूरी है कि नीतीश कुमार अपनी कामयाबी का सूत्र कहां देख रहे हैं।

खगड़िया में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरा, मुख्यमंत्री सख्त

प्रातः किरण संवाददाता

पटना। खगड़िया के अगुवानी–सुल्तानगंज के बीच गंगा पर बन रहा पुल रविवार को गिर गया। पुल के चार पिलर भी नदी में समा गए। पुल का करीब 192 मीटर हिस्सा नदी में गिरा है। हादसे के समय मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। पुल का कुछ हिस्सा पिछले साल भी गिर चुका है। इसे एसपी सिंगला कंपनी बना रही है। पुल को शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। इसकी लागत 1710.77 करोड़ रुपए है। पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। पुल का बड़ा स्ट्रक्चर गंगा में गिरने से 50 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठीं। इससे नाव से सफर कर रहे लोग दहशत में आ गए। किसी तरह से नावों को किनारे लाकर लोगों को निकाला गया।

इस निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर पिछले साल भी नदी में गिर गया था। तीन पिलर्स के 36 स्लैब यानी करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भरभराकर ढह गया था। रात

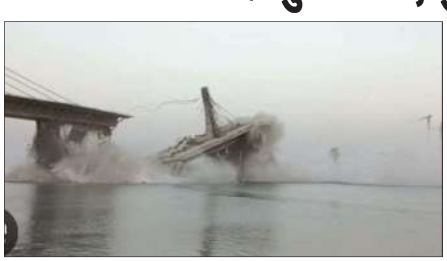

में काम बंद था, इसलिए जनहानि नहीं हुई थी। उस समय पुल निगम के एमडी के साथ एक टीम ने वहां जाकर जांच भी की थी।

प्रोजेक्ट पूरा होने पर झारखंड से जुड़ जाएगा उत्तर बिहार: ये पुल अगुवानी और सुल्तानगंज घाट (भागलपुर जिला) के बीच बन रहा है जो बरौनी खगड़िया एनएच 31 और दक्षिण बिहार के मोकामा, लखीसराय, भागलपुर, भिजाचौकी एनएच 80 को जोड़ेगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर बिहार के खगड़िया की ओर से 16 किलोमीटर और सुल्तानगंज की ओर से चार किलोमीटर लंबी एप्रोच रोड के जरिए उत्तर बिहार सीधे भिजा चौकी के रास्ते झारखंड से जुड़ जाएगा। पुल बनने से खगड़िया से भागलपुर आने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर रह जाएगी।

मुख्यमंत्री ने घटना की जांच कराने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने का दिए निर्देश: खगड़िया – अगुवानी – सुल्तानगंज के बीच निर्माणाधीन महासेतु के सुपर स्ट्रक्चर के ऊपरी हिस्से के टूटकर गिरने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मामले की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग को पुल के सुपर स्ट्रक्चर टूटकर गिरने की घटना की विस्तृत जांच कराने और दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

फेस ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी करने में बिहार अग्रणी

- ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले लाभार्थी किसान 14 वीं किस्त से हो सकते हैं वंचित

प्रातः किरण संवाददाता

पटना। भारत सरकार द्वारा फेस ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी कराने की शुरूआत की गई है। 02 जून तक पूरे देश में 97,134 किसानों का फेस ऐप से ई-केवाईसी सत्यापन हुआ है। उक्त जानकारी कृषि विभाग द्वारा दी गई है। जारी बयान में बताया गया है कि बिहार से 41,357 किसानों का फेस ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी सत्यापन किया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल में 32,114, आंध्र प्रदेश में 7,175 और उत्तर प्रदेश में 7,135 किसानों का इस प्रक्रिया से सत्यापन किया गया है। इस प्रकार, फेस ऐप से ई–केवाईसी करवाने में बिहार अग्राणी राज्य है। राज्य के 83,68,590 पंजीकृत किसानों में से 70, 97,051 किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवश्यक ई–केवाईसी करवा लिया है। इस प्रकार, 85 प्रतिशत लाभार्थी किसानों द्वारा अभी तक अपना ई–केवाईसी करा लिया गया है, जबकि 12,71,539 लाभार्थी किसानों द्वारा ई–केवाईसी सत्यापन किया जाना शेष है। किसान से अपील है कि वे अपना ई–केवाईसी कराने के लिए फेस ऐप/किसान सीएससी सेंटर पर बायोमैट्रीक के माध्यम से या फिर पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर ओटीपी के माध्यम से ई–केवाईसी का सत्यापन यथा शीघ्र करवा ले।

संक्षिप्त खबरें

राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर रवाना

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सूरीनाम और सर्बिया की पहली राजकीय यात्रा के लिए रवाना हुईं। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद यह उनकी पहली राजकीय यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निर्वाचन पर चार से छह जून तक पारामारिबो में रहेंगी। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में वह सात से नौ जून तक सर्बिया की यात्रा पर जायेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर पांच जून को आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति सूरीनाम के अपने समकक्ष संतोखी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगी। वह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का भी दौरा करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों और प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगी।

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को तीन साल बाद मिला पासपोर्ट

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को तीन साल बाद 10 वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट जारी किया गया है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद महबूबा को पासपोर्ट मिल गया है। उनके पासपोर्ट की वैधता 2019 में समाप्त हो गई थी और वह तभी से इसके नवीनीकरण की मांग कर रही थीं। महबूबा को ऐसे समय में पासपोर्ट जारी किया गया है, जब दो दिन बाद जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में उनकी बेटी इल्तिजा की याचिका पर सुनवाई होगी है, जिसमें उन्होंने खुद को देश विशिष्ट पासपोर्ट देने के पासपोर्ट कार्यालय के फैसले को चुनौती दी है। महबूबा को दिए पासपोर्ट की वैधता एक जून 2023 से 31 मई 2033 तक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल मार्च में पासपोर्ट प्राधिकरण से पीडीपी प्रमुख को नया यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए तीन महीने के भीतर फैसला लेने को कहा था।

मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग नियुक्त किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने, एनएच-2 राजमार्ग से नाकेबंदी हटाने की अपील की है, ताकि लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। गृह मंत्रालय ने रविवार को मणिपुर में जातीय संघर्ष की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच आयोग बना दिया। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। आयोग की अध्यक्षता गौहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा करेंगे। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस आलोक प्रभाकर आयोग के सदस्य होंगे। अमित शाह ने ट्वीट किया, हमारिपुर के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि इंफाल-दीमापुर, एनएच-2 राजमार्ग पर लगे अवरोधों को हटा लें।

80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा निशुल्क राशन : रविशंकर

प्रातः किरण /एजेंसी

पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने केन्द्र सरकार के 9 साल को बताया बेमिसाल

पटना। भाजपा नेता केंद्र सरकार के 9 साल को बेमिसाल बता रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, नितिन नवीन सहित कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार की उपलब्धियों को बताया। रविशंकर प्रसाद ने उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि 80 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है।

200 करोड़ लोगों को कोरोना का मुफ्त टीका दिया। 45 करोड़ जनधन खाते खोले गए 27 लाख करोड़ गरीबों के खाते में सहायता राशि दी गई। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरर में दुनिया में दूसरा नंबर पर है। कश्मीर में तिरंगा लहराया जा रहा है और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक लाख 40 जाहर करोड़ का हिसाब बिहार को केंद्र सरकार ने दिया। बिहार में

दो एम्स है दो केंद्रीय विद्यालय है अन्य राज्य में एक होता है। बिहार से 6000 किलोमीटर नेशनल हाईवे गुजर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 38 लाख 62 हजार 734 घरों की सिक्योरिटी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार का आवंटित किया गया है। बिहार के किसानों को 16 हजार करोड़ दिए गए हैं। पटना का गांधी सेतु 1742 करो रुपए खर्च किए गए पुनर्निर्माण के लिए जो केंद्र ने दिया। केंद्र सरकार ने जिन जिन क्षेत्रों में निर्माकरण किया उन सभी क्षेत्रों को सुधारने के लिए काम किया है। बालासोर रेल दुर्घटना पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री घटनास्थल पर मौजूद रहे है। कांग्रेस ने कहा था इस मामले पर राजनीति नहीं करेंगे आज से शुरू कर दिया।

लालू प्रसाद यादव रेलवे पर बोल रहे हैं। आपके समय में क्या हुआ उसकी जांच सीबीआई कर रही है। विपक्षी एकता को लेकर पटना में होने वाली बैठक पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी भारत को तोड़ने वाली पार्टी मुस्लिम लीग को सेकुलर कहती है कम्युनल नहीं नीतीश कुमार इस पर अपनी राय प्रकट करें।

रक्षा मंत्री 5-6 जून को अमेरिकी और जर्मन समकक्षों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे

जून में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले ऑस्टिन की भारत यात्रा अहम

प्रातः किरण /एजेंसी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस नई दिल्ली आ रहे हैं। रक्षा मंत्री 05 जून को अमेरिकी रक्षा मंत्री और 06 जून को जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर बातचीत करेंगे। दोनों बैठकों के दौरान औद्योगिक सहयोग पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा सचिव 04 जून को सिंगापुर से दो दिवसीय दौरे को पूरा करके भारत आएंगे। यह ऑस्टिन की दूसरी भारत यात्रा होगी। वह पहली बार मार्च, 2021 में भारत की यात्रा पर आए थे। जून में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिकी राजकीय यात्रा को देखते हुए ऑस्टिन की इस यात्रा को अहम माना जा रहा है। ऑस्टिन की नई दिल्ली यात्रा प्रमुख रूप से भारत–अमेरिका के नए रक्षा नवाचार और औद्योगिक सहयोग की पहल को आगे बढ़ाने और अमेरिका एवं भारतीय सेनाओं के बीच परिचालन सहयोग का विस्तार करने के प्रयासों को जारी रखने पर केंद्रित होगी।

जर्मनी के रक्षा मंत्री 05 जून से भारत की चार दिवसीय यात्रा पर आएंगे। वह इंडोनेशिया से भारत आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक करने के अलावा बोरिस पिस्टोरियस नई दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ रक्षा स्टार्टअप से भी मुलाकात करेंगे। वह 07 जून को मुंबई जाएंगे, जहां वह पश्चिमी नौसेना कमान और माइसगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के मुख्यालयों का दौरा करेंगे।

खड़गे का आरोप- केन्द्र सरकार रेल सुरक्षा की कर रही अनदेखी

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना के दो दिन बाद इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर रेलवे सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आए दिन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने में व्यस्त रहते हैं और उनका रेलवे सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। रेलवे में ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी जवाबदेही तय करनी जरूरी है। इसी से भविष्य में इस तरह के हादसे रुकेंगे और पीड़ितों को न्याय मिलेगा।

खड़गे ने कहा कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा और दर्दनाक रेल हादसा है। मोदी सरकार 'पीआर' पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उन्होंने पूछा कि रेलवे में 3 लाख से अधिक पद खाली हैं और उन्हें अभी तक क्यों नहीं भरा गया। खड़गे ने रेलवे बोर्ड की मानव संसाधन की कमी को स्वीकारने और सिग्नल व्यवस्था को लेकर पूछा कि रेल मंत्रालय ने इन पर अमल क्यों नहीं किया। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने संसदीय समिति की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भी आरोप लगाया कि कई खामियों को समय रहते दूर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा आयोग केवल 8 से 10 प्रतिशत हादसों की ही जांच क्यों करता है। 2017–18 से 2020–21 के बीच 10 में से लगभग 7 रेल दुर्घटनाएं रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की वजह से हुई हैं। रेलवे राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की फंडिंग में 79 प्रतिशत की कमी क्यों की गई है।

ओडिशा रेल हादसा राज्य मुख्य सचिव पी के जेना ने रविवार को दुर्घटना में 275 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की।

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव ट्रेन दुर्घटना का कारण : वैष्णव

प्रातः किरण /एजेंसी

भुवनेश्वर/नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में बालासोर जिले के बहानगा में ज़ुक्रवार को हुए भीषण ट्रेन हादसे के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। राज्य मुख्य सचिव पी के जेना ने रविवार को दुर्घटना में 275 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक शव की दो बार गिनती और गिनती के दौरान कुछ अन्य गलतियों के कारण शनिवार को मृतकों की संख्या 288 हो गई थी। श्री जेना ने कहा कि अब तक 275 शवों में से 88 की पहचान की जा चुकी है। मुख्य सचिव ने कहा कि 170 शवों की पहचान के लिए भुवनेश्वर लाया गया और बाद में मृतकों के परिजनों और रिश्तेदारों को सौंप दिया गया जबकि 17 और शवों को लाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि 88 शवों में से 78 को पहले ही उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है और बाकी 10 शवों को उनके रिश्तेदारों को सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने भीडियाकर्मियों से कहा कि दुर्घटना के मूल कारण की पहचान कर ली गई है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की भी पहचान कर ली गई है। हादसे की जांच पूरी हो चुकी है और रेल सुरक्षा आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उन्होंने कहा कि दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव के कारण हुई और रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चहानगा रेलवे स्टेशन पर मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। श्री वैष्णव, जो दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं और व्यक्तिगत रूप से शनिवार से बहाली के काम की निगरानी कर रहे हैं, ने कहा कि बहाली का काम पूरा करने और बुधवार सुबह तक ट्रेन की आवाजाही को सामान्य करने का लक्ष्य रखा गया है। मरम्मत कार्य में करीब एक हजार कर्मचारी लगे हुए हैं। शालीमार–चेन्नई कॉमंडल एक्सप्रेस शुक्रवार शाम बालासोर जिले के बहानगा रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी और बेंगलुरु–हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकरा गई जिसके कारण यह हादसा हुआ।

ओडिशा ट्रेन हादसे की समयबद्ध जांच के लिए शीर्ष अदालत में याचिका: ओडिशा रेल हादसे की समयबद्ध जांच उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले एक विशेषज्ञ आयोग से कराने का निर्देश देने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि यह दुर्घटना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और नागरिकों की स्वतंत्रता के उल्लंघन के मद्देनजर उच्च अधिकारियों द्वारा की गई घोर लापरवाही को

मोदी ने फोन पर पटनायक से ताजा स्थिति की ली जानकारी

भुवनेश्वर/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल दुर्घटना संकट के दौरान त्वरित और कुशल कार्रवाई के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि श्री मोदी ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर केंद्र किसी भी तरह की सहायता देने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में जिस तरह के सहयोग और समय पर मदद के लिए ओडिशा के लोगों की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि ओडिशा के विभिन्न अस्पतालों में घायल यात्रियों को जान बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर, मेडिकल छात्र जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। घायल व्यक्तियों के लिए रक्तदान करने के लिए डॉक्टर, छात्र और आम लोग आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी नीति का पालन करते हैं जो हर जीवन कीमती है को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान से लेकर घायलों को अस्पताल ले जाने, इलाज की व्यवस्था करने तक, हम जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ताजा स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि विभिन्न अस्पतालों में 1175 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 793 को छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर घायल मरीजों की हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 382 यात्रियों का विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

दशमी है। दो जून को हुए हादसे में 288 लोगों की मृत्यु और 1000 से अधिक लोगों के घायल हो गये हैं। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर इस याचिका में भारतीय रेलवे प्रणाली की मौजूदा जोखिम और सुरक्षा मानकों का विश्लेषण और समीक्षा करके इसे मजबूत करने के लिए व्यवस्थित सशोधनों का सुझाव देने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा व्यवस्था (एटीपी) कवच लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश भी मांग की है। ट्रेन संचालन की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में इस मत्वपूर्ण कदम की घोषणा रेल मंत्रालय ने 23 मार्च 2022 को की थी। श्री तिवारी ने अपनी याचिका में कहा है कि उच्च अधिकारियों द्वारा बार–बार इस तरह (रेल हादसा) की अनियमित और लापरवाहीपूर्ण कार्यवाहियों के साथ ही सख्त न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। याचिका में ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में तीन ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त होने से 288 से अधिक लोगों की मौत और 1000 से अधिक लोग घायल तथा इससे सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान होने का जिक्र है। याचिका में कहा गया है कि यह हादसा पिछले कुछ दशकों में भारत में सबसे बड़े रेल हादसों में से एक है।